(1300/RAJ/RCP)

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका ध्यान अतिमहत्वपूर्ण विषय 28-खीरी लोक सभा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तहसीलों में हरिजन कल्याण विभाग, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट पुनर्वास द्वारा विस्थापित बंगालियों, हरिजनों और जनजातियों से संबंधित किसानों को भूमिधरी अधिकार दिलाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। 28-खीरी लोक सभा की तहसील पलिया में गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट में आवंटित कर 12 कालोनियां बसाई गई थीं - गोविन्द नगर, भानपुरी, कमलापुरी, कृष्णा नगर, बसही, रानी नगर, मुरारखेड़ा, सुमेर नगर, इब्राहिमपुर, विचित्र नगर, विशेनपुरी गिरधरपुर कालोनियां। हरिजन समाज कल्याण द्वारा तहसील गोला में कुसमौरी कालोनी, भटरपुरवा कालोनी, तहसील मोहम्मदी की साहबगंज कालोनी, तहसील लखीमपुर में नकाब पीपरी कॉलोनी, पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित बंगाली शरणार्थियों को आवंटित भूमि तथा पलिया व निघासन तहसील में थारू जनजाति को भूमि आवंटित की गई थी। इनको जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश में भूमि का अधिकार दिलाने की कृपा करें।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : श्री राजू बिष्ट जी, आप अपनी बात एक मिनट में रखिए।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : सर, नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुर द्वारा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा, इन आठ जिलों की जनसंख्या करीब आठ करोड़ है। डेवलमेंट की दृष्टि से और स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से, ये बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। वहां ज्यादातर हमारी जनता चाय बगान पर काम करती है या कृषि से उनका जीवन चलता है। नॉर्थ बंगााल की स्थिति आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी नहीं रही है। जहां तक प्राइवेट अस्पताल की बात करें, तो वहां पर हमारी जनता को जा कर अपना इलाज कराना संभव नहीं हो पाता है। जहां तक पश्चिम बंगाल की जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। वहां डॉक्टर्स और स्टाफ का अभाव रहता है। खास कर, नॉर्थ बंगाल में जो बेसिक इक्विप्मेंट्स उपलब्ध होने चाहिए, वे उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल की स्थिति और भी ज्यादा खराब है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि नॉर्थ बंगाल के लिए, तीन करोड़ जनता के लिए एक एम्स की व्यवस्था की जाए।

MD. RAKIBUL HUSSAIN (DHUBRI): Sir. I rise today to draw your attention to a long-standing and pressing issue that affects millions of people in the State of Assam, particularly the Adivasi or Tea Tribes, along with the Chutia, Koch-Rajbongshi, Matak, Moran, and Tai-Ahom communities.

The demand for a Scheduled Tribe status for these communities is not new. It has been consistently raised by various social organisations, intellectuals, political leaders, and representatives from these communities. In 2014, the BJP declared that after coming to power, within 100 days, they would declare all these six communities as Tribal communities in the State of Assam.

It has been a decade, but no promise has been fulfilled like other *jumlas*. Yet, the Government has not taken concrete steps to address this demand.

I would request the Government to declare all these communities as tribal communities in the State of Assam.

Thank you.

श्री गोडम नागेश (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, मेरी मांग मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद, तेलंगाना में हवाई अड्डे की स्वीकृति के लिए है। मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद में बहुत वर्षों से यह मांग की जा रही है। हाल ही में, मंत्री महोदय ने एक बयान में भी कहा है कि आदिलाबाद एक स्ट्रैटजिक लोकेशन है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए यह हवाई अड्डा बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी राज्य सरकार को प्री-फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट के बारे में कहा है, लेकिन अब तक हमारे राज्य तेलंगाना से फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत ही हमारे राज्य सरकार से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवा कर, जल्द से जल्द आदिलाबाद में हवाई अड्डे की स्वीकृति दें। धन्यवाद।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, unaccountable money has been recovered from one of the judges of the Delhi High Court. This is not only the last one incident. The factum of recovering money from the High Court Judge is really eroding the confidence on Judiciary. Judges are also public servants like us.

(1305/PS/SK)

Why will any investigation not commence if a complaint of corruption is made against a judge? Irrespective of the fact that the Chief Justice of India grants permission or not, will it be commenced? If a corruption is there, will it be commenced? Recovery of money is there. These types of instances are there. Why will Lokpal be not allowed to carry on an investigation if a complaint comes against a judge who is a public servant like us?

Here, a judge has been transferred from the Delhi High Court to the Allahabad High Court. This will not resolve the problem. I share the sentiments of the lawyers of the Allahabad High Court. The Allahabad High Court or the Calcutta High Court cannot be a dumping ground. Corrupt judges are there. All complaints are there. They are being transferred to the Calcutta High Court or Allahabad High Court. It should not be made a dumping ground.

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr. Chairperson, Sir, I would like to continue from where my hon. colleague, Mr. Kalyan Banerjee, left off.

The reports about the alleged aberrations in the Judiciary have disturbed the conscience of all right-thinking citizens across the country. However, it is too premature to apportion guilt or otherwise. However, Mr. Chairperson, this House, the Parliament, is charged with the responsibility of exercising superintendence over the Judiciary. It is charged with the responsibility of exercising oversight over the Judiciary.

The Chief Justice of India has appointed an in-house inquiry. I think we should respect the process. We should wait for that report. But in the meanwhile, the Law Minister should come to this House and he must relate the chronology of events as they have transpired. Nobody is saying that anyone is innocent or guilty. Nobody is trying to apportion guilt. Let the in-house inquiry process play itself out. But under Articles of the Constitution and the Judges (Inquiry) Act, this Parliament has the responsibility of exercising that superintendence. And we are abrogating our responsibility.

My demand is, let the Law Minister come before the House and make a vanilla statement as to what is the sequence of events; what actually transpired; what does the Government know. Why is the Government not making a statement before the House?

Thank you, Mr. Chairperson.

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : माननीय सभापति जी, हमारे यहां रेलवे के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, वहां रेल यात्रियों की संख्या अधिक है और इस कारण लोगों को बाहर आने-जाने काफी दिक्कतें होती हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पटना से पूर्णिया तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, जो सहरसा-मधेपुरा होकर गुजरे ताकि इस इलाके के लोगों को ट्रेन की सुविधा मिल सके।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : माननीय सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक ऐसे गांव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आप सबको आश्चर्य होगा। यहां अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, जलंधर के पास संसारपुर नाम का गांव है। एक ही गांव के 14 ओलम्पियन्स हैं, सात ओलम्पिक्स में मेडल हैं, जिनमें चार गोल्ड, एक सिल्वर और दो ब्रोन्ज हैं।

(1310/KN/SMN)

इतना ही नहीं, वर्ष 1975 में भारत ने जो हॉकी का विश्व कप जीता था, उसके कैप्टन अजीत पाल सिंह वहीं के थे। सारे के सारे ओलंपियन्स एक ही गली में रहने वाले और एक ही गोत्र-कुलार के हैं। लेकिन वर्ष 1976 के बाद उस गांव में से एक भी ओलंपियन नहीं मिला और एक भी मैडल नहीं मिला। उसका कारण है कि वह गांव, जालंधर एरिया का जो कैंट का एरिया है, उसकी बगल में है।

उस गांव के पास न तो अपनी पंचायत की जमीन है और न ही ग्राउंड है। वे सारे बच्चे आर्मी एरिया के ग्राउंड में खेलते थे और वहां से खेलकर ओलंपिक तक पहुंच गए। लेकिन वर्ष 1976 के बाद हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर चली गई और ग्रांउड वही ग्रास का रह गया। … (व्यवधान) सर, एक मिनट दीजिए। यह विषय बहुत जरूरी है। पचास साल हो गए हैं। न तो आर्मी से एनओसी मिली और न ही आर्मी ने वहां एस्ट्रोटर्फ लगाने की अनुमति दी। मेरा सरकार से आग्रह है कि जिस ग्राउंड ने हमें 14 ओलंपियन्स दिए, 7 ओलंपिक के मैडल्स दिए। क्या हम वहां एक एस्ट्रोटर्फ नहीं दे सकते हैं? मेरा गृह मंत्री जी, खेल मंत्री जी और अनुराग जी से आग्रह है कि वहां कृपया एस्ट्रोटर्फ लगाई जाए, ताकि एक बार फिर से वहां ओलंपियन पैदा हो सकें।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : श्री जितेंद्र कुमार दोहरे जी।

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिये। अनुराग जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। संसारपुर से हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी आते रहे हैं। उसके पास ही जालंधर कैंट में बीएसएफ का सेंटर है, वहां पर मोदी सरकार ने 7.5 करोड़ रुपये खर्च करके एस्ट्रोटर्फ लगा दी है। मेरा अनुरोध यह रहेगा कि हम बीएसएफ वालों से बात भी कर लेंगे, ताकि वे स्थानीय खिलाड़ियों को वहां खेलने का अवसर दें। माननीय मंत्री जी से हम भी आग्रह करेंगे कि और भी सेंटर बन सके। अगर सरकार जमीन उपलब्ध करवाए तो वह काम करवाएंगे।

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे इटावा लोक सभा क्षेत्र में गेल-गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित है, जहां पर भू-विस्थापित लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। जब गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित हुई थी तो उस टाइम किसानों से यह वायदा किया गया था कि हम हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। लेकिन वहां के अधिकारियों ने बाहर से नए-नए ठेकेदारों को बुलाकर अपने चहेतों को रोजगार देने का काम किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए। इतना ही नहीं, वहां के अधिकारी लोग अपने तरीके से, रिश्वत लेकर एक गांव में 5 करोड़ रुपये से ऊपर सीएसआर के द्वारा पैसा लगाया गया, जिसकी जांच हम करवाना चाहते हैं। मैं आपसे यही मांग करता हूं कि वहां के सभी भू-विस्थापित लोगों को रोजगार देने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वूपर्ण विषय रखना चाहता हूं। त्रिपुरा छोटा स्टेट है, आर्थिक रूप से कमजोर है और केन्द्र सरकार के ऊपर निर्भर है। वहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। प्राइमरी सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो सकता है। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि त्रिपुरा में एक आईआईएम या आईआईटी के जो संस्थान हैं, वहां प्रतिष्ठित करने का काम करें। इसमें आस-पास की स्टेट से भी आकर विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। त्रिपुरा में जब ऐसे इंस्टीट्यूशन्स होंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के जो ऐसे छोटे-छोटे स्टेट हैं, उनको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का एकमात्र उपाय एजुकेशन

इंस्टीट्यूशन है। त्रिपुरा की लिटरेसी रेट भी लगभग 98 परसेंट है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यही आग्रह करूंगा कि आईआईएम या आईआईटी में से कोई एक इंस्टीट्यूशन देने की व्यवस्था करे। धन्यवाद।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में कुल 731 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जिनमें आईसीएआर, राज्य विश्वविद्यालय एवं एनजीओ शामिल हैं। इसमें कुल मिलाकर लगभग 11 हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। जो विभिन्न प्रकार के कार्य प्रदर्शन, प्रशिक्षण, समसामयिक कृषि सलाह, मौसम संबंधी सूचना, उन्नत कृषि तकनीक, कौशल विकास प्रशिक्षण, मैदानिक सलाह, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि और कृषकों के बीच बांध का कार्य करते हैं। वे नई-नई तकनीक कृषकों तक सीधे पहुंचाते हैं और उनकी आय दोगुना करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

(1315/VB/SM)

कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि से संबंधित समस्त कार्य करते हैं, जिससे राज्यों के कृषक कृषि, पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। इनमें बहुत से प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार और सम्मान में धनराशि से नवाज़ा गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से, कृषकों को राज्य एवं केन्द्र के स्तर पर सम्मान प्राप्त हो चुका है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त न होने की स्थिति में वे अपने कार्य शत-प्रतिशत नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों तथा कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। कृषि विज्ञान केन्द्रों के समस्त अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। इस प्रकार वेतन प्राप्ति में विलम्ब होने से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है तथा उनके ऊपर आश्रित परिवारों का जीवन संकट की स्थिति में है। इस परिस्थिति के कारण कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है।

अत: मेरी मांग है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए पूर्व की भाँति तत्काल वेतन प्रदान कराने का कष्ट करें। कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत समस्त प्रक्षेत्र प्रबंधकों को वैज्ञानिकों का दर्जा देते हुए, विषय-वस्तु विशेषज्ञ की भाँति समस्त वेतनमान एवं भत्ते भी प्रदान किये जाएं। इनको पिछले छ: माह से अधूरे वेतन, पेंशन, चिकित्सा भत्ता आदि नहीं दिये जा रहे हैं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

*SHRI BALWANT BASWANT WANKHEDE (AMRAVATI): Hon'ble Chairman, CCI started procuring cotton barely too months ago and it stalled the procurement process since 15th March abruptly. In Marathwada and Khandesh region, CCI is stalling the procurement process assigning various reasons. It is being done in Vidarbha region but at a very slow pace and there is no continuity.

* Original in Marathi

Sir, the process started very late and that is why the farmers sold the cotton in open market at cheaper rates and they had to suffer losses.

I request to streamline the procurement process. Cotton should be procured without any gradation. The last date for registration is 15/03/2025 and it must be extended immediately.

So, I would request you to kindly look into it.

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे कानपुर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, कानपुर एक औद्योगिक शहर है। उत्तर प्रदेश में यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। आज कानपुर की आबादी लगभग 60 लाख से अधिक है। अंग्रेजों के जमाने में, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर देश के पाँच बड़े शहरों में शामिल था। लेकिन कानुपर की मिलें बंद हो चुकी हैं। कानपुर में लगभग एक दर्जन बीआईसी और एनटीसी की मिलें हैं, जो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं।

महोदय, कानपुर के बीचोंबीच मिलों के खंडहर कानपुरवासियों को चिढ़ा रहे हैं। ये कानपुर के माथे पर कलंक हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कानपुर की बंद मिलें, जो चालू हो सकती हैं, उनको चालू कराया जाए और जो चालू नहीं हो सकती हैं, उनमें आईटी हब या ऐसी किसी रोज़गार की स्कीम दी जाए ताकि कानपुर के लोगों को रोजगार मिल सके।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उन मिलों को चालू किया जाए और इसके साथ ही, लाल इमली मिल के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भी भुगतान कराया जाए।

धन्यवाद।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak in the 'Zero Hour'.

Shri Sabir Mallik, a young boy from Basanti in my Parliamentary Constituency of Jaynagar, went to Charkhi Dadri district of Haryana in search of a job as a migrant labour. He was brutally killed by some local *Hindutvadi* activists, who falsely blamed him for having consumed beef.

(1320/PC/RP)

सर, हरियाणा गवर्नमेंट से न दोषी को कोई सजा मिली और न ही उनसे कोई मदद मिली। न ही ठेकेदार को उनका कुछ पैसा दिया।

सर, श्री साबिर मलिक की बॉडी पश्चिम बंगाल ले जाने के लिए उसके परिवार को एंबुलेस पर 70,000 रुपए खर्च करने पड़े। Are the Muslims not the citizens of our country? Is this 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' or *amritmaya* Bharat?

मैं Ministry of Social Justice and Empowerment से दरख्वास्त करना चाहती हूं कि उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : श्री प्रवीण पटेल जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मान्यवर, मुझे गर्व है कि मैं प्रयागराज जिले से आता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही इलाहाबाद हाई-कोर्ट स्थित है, इसका भी हम लोगों को बड़ा गर्व है। निश्चित रूप से बड़ी निराशा हुई, क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई-कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति के घर में रुपए जलाने की खबरें आई थीं। उसके बाद माननीय जज साहब को इलाहाबाद हाई-कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसको लेकर इलाहाबाद हाई-कोर्ट की बार एसोसिएशन से लेकर सारे अधिवक्ता और केवल इलाहाबाद हाई-कोर्ट ही नहीं, बल्कि 20 जनपदों के कोर्ट्स के अधिवक्ता आज आंदोलित हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जरूर इस बात को कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका हमारे संविधान का एक ऐसा स्तंभ है, जिसके प्रति लोगों का बड़ा अटूट विश्वास है। निश्चित रूप से ऐसा विश्वास जब टूटता है, तो लोगों के अंदर एक निराशा पैदा होती है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जरूर इस बात को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री उम्मेदा राम बेनीवाल जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के एक विशेष मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की पाकिस्तान से लगी हुई सीमा की तारबंदी वर्ष 1952 में हुई थी। जीरो-पॉइंट और तारबंदी के बीच में किसानों के खेत आए हुए हैं। इससे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर की 1,050 किलोमीटर की सीमा के अंदर के किसान काफी प्रभावित हुए हैं। जीरो-पॉइंट से तारबंदी के बीच में किसानों को न तो जमीन का मुआवजा दिया गया और न ही खेती करने की परमीशन दी गई।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि या तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए या उनको खेती करने की परमीशन दी जाए। जैसे पंजाब के अंदर किसानों को जीरो-पॉइंट और तारबंदी के बीच में खेती करने की अनुमति दी गई है, वैसे ही मेरे क्षेत्र के किसानों को भी परमीशन दी जाए।

धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दनियावां-बिहार शरीफ रेल खंड पर कुकरिया गांव में अंडरपास अथवा ओवरब्रिज का निर्माण अति-आवश्यक है। माननीय रेल राज्य मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। हम लोग विकास के लिए लगातार प्रयास करते हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कुकरिया गांव है, वहां दनियावां-बिहार शरीफ रेल खंड चालू है। वहां पर काफी स्कूल्स हैं, उच्च विद्यालय बमपुर है और निकटतम जितने भी गांव हैं, वहां पर कोई आवागमन नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, माननीय रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, कि दनियावां बिहार शरीफ रेल खंड पर कुकरिया गांव में अंडरपास की सुविधा दे दी जाए या ओवरब्रिज बना दिया जाए, जिससे वहां पर आने-जाने वालों को सुविधा हो सके।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1908 से वर्ष 1913 के बीच में राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा पर मानगढ़ धाम आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में गोविंद गुरू जी के नेतृत्व में भील भक्तों ने वैदिक हवन, यज्ञ, महादेव की भक्ति, गुरू भक्ति, पूर्णिमा का मेला और भगवा ध्वज लेकर सामाजिक समरसता के आधार आंदोलन किया था।

महोदय, यहां जो गीत गाए गए उनमें भारत को जाम्बू खंड और दिल्ली में कलम है, ऐसा एक प्रतीकात्मक गीत भी गाया गया। ऐसा लगता है कि उसमें इकोसिस्टम, जो औपनिवेशिक सत्ता का था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन था।

(1325/CS/VR)

मेरा निवेदन यह है कि यहाँ जो आदिवासी सनातनी भगत हुए हैं, उनकी शहादत की गाथा पूरे विश्व के सामने नहीं आ पायी है। मेरा यह आग्रह है कि भारत की दृष्टि से स्वाधीनता का जो भाव है, उसको लेकर लेखन हो, उस गाथा का प्रकाशन हो, यहाँ तक कि वेब सीरीज भी बनायी जा सकती है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अल्लूरी राजू और कोमराम भील के आधार पर एक फिल्म 'आरआरआर' आयी थी, उसी तरीके से इसमें एक बड़ा काम हो सकता है। ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, Dr. Siddhartha Mukherjee in his book 'The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer' wrote:

> "Cancer is an expansionist disease; it invades through tissues, sets up colonies in hostile landscapes, seeking "sanctuary" in one organ and then immigrating to another."

This disease devastates not only the patient but his family and finance as well. The financial toxicity of cancer care in India is a matter of grave national concern. Every year, millions of Indians are pushed into poverty while battling cancer. Precision medicine, immunotherapy, and targeted treatments remain out of reach for low and middle-income families. A genomic test can save a patient, but most of them cannot afford it.

Public insurance schemes including Ayushman Bharat cover only inpatient costs for cancer treatment, leaving diagnostic tests, outpatient care, and posttreatment expenses to be paid out-of-pocket. Many affected families sell all their all assets and exhaust their savings, yet the survival remains uncertain.

Hence, I urge the Government to introduce a Universal Cancer Insurance Scheme, covering full treatment and non-medical costs. Cancer must not be a death sentence for the poor. Thank you, Sir.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज उत्तर बिहार का एक प्रमुख लोक सभा क्षेत्र है। हमारे संसदीय क्षेत्र सहित इसके आसपास के कई संसदीय क्षेत्रों की जनता की जीविका का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। ऐसे मैं स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों में अपने बच्चों को पशु चिकित्सा संबंधी उच्च शिक्षा दिलवाने की आकांक्षा होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलवाया जाए। वैसे भी बिहार राज्य में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की कमी है। इस परिस्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तर बिहार के अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को पशु चिकित्सा संबंधी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य बनाने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही पशुधन आबादी वाले बड़े क्षेत्र में पशुओं, पक्षियों के स्वास्थ्य की भी देखभाल होगी।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलवाने की कृपा की जाए। धन्यवाद।

डॉ. नामदेव किरसान (गड़चिरोली-चिमुर) : सर, मेरे गड़चिरोली-चिमुर संसदीय क्षेत्र में और गड़चिरोली जिले में एक मारकंडेश्वर देवस्थान है। इस मारकंडेश्वर देवस्थान का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 10 साल पहले अपने हाथ में लिया था, लेकिन अभी तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। वह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। यह काम जल्द से जल्द पूरा हो। श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए यह काम जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिए जाएं कि वह इस काम को जल्द से जल्द पूरा करे। धन्यवाद।

(1330/AK/IND)

श्री चरनजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पंजाब में चमड़े के कारोबार और लैदर इंडस्ट्री के हालात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब में खास तौर से जालंधर चमड़े के कारोबार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि फुटबॉल चमड़े से बनती है और चमड़े का कारोबार पंजाब में बंद हो गया है इसलिए यह इंडस्ट्री बैठती जा रही है। जितनी हड्डा-रोड़ियां थीं, वे बंद हो गई हैं। कोई भी जानवर यदि मर जाता है, तो उनके शरीर को संभालने के लिए कोई हड्डा-रोड़ियां नहीं हैं। जालंधर में चमड़े का कारोबार बंद होने के कागार पर पहुंच चुका है। विदेशों से जो चमड़ा आता है, उस पर आयात शुल्क बहुत कम कर दिया

गया है, जिसकी वजह से हमारे यहां चमड़े का कारोबार करने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाहर से सस्ता चमड़ा उपलब्ध हो रहा है और हमारा यहां का चमड़ा महंगा होने के कारण उतनी लागत नहीं निकल पाती है। यहां तक कि हमारे यहां चमड़े की उपलब्धि ही नहीं है। जो पशु मरते हैं, उनके लिए किसी को ठेका नहीं दिया जाता, कोई हड्डा-रोड़ी का इंतजाम नहीं है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि पंजाब में मर रही चमड़ा इंडस्ट्री को संभाला जाए।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलराम पुर जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश एवं देश में आज छुट्टा जानवरों की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। छुट्टा जानवरों की वजह से किसानों और आम जन-मानस को काफी परेशानी हो रही है। किसानों के खेतों में तैयार खड़ी फसलों को ये आवारा पशु नष्ट कर देते हैं और किसानों को इस नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलता है। किसान दिन-रात खेतों में रहकर अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। ये आवारा पशु, जैसे नील गाय अचानक सड़कों पर आ जाती हैं, इस कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली जाती है। कई मोहल्लों, कस्बों, बाजारों और शहरों में इन आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके साथ-साथ राहगीरों पर इनके द्वारा हमले का खतरा भी बना रहता है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से मांग करता हूं कि छुट्टा जानवरों को रोकने और उनके आवास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराया जाए और इन गौशालाओं में खाने के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी देखभाल के लिए अन्य सभी जरूरतों का भी उचित प्रबंध किया जाए, जिससे किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके और इनके कारण आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोका जा सके।

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): Chairperson Sir, thank you for giving me this opportunity.

I seek to raise an urgent matter concerning the agricultural sector in my Tenkasi constituency, which requires immediate intervention from the Government.

Tenkasi is a major producer of mango, lemon, bananas, and coconut, yet farmers face severe post-harvest losses due to the lack of modern storage and food processing facilities. This has led to distress sales, reduced income for farmers, and missed opportunities for value addition.

The Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) under the Ministry of Food Processing Industries provides financial assistance for setting up food processing clusters to support infrastructure development, processing units, cold storage, and logistics. However, Tenkasi has not been included in the scheme despite its agricultural potential.

A dedicated food processing cluster in Tenkasi will enhance farmers' income by reducing wastage and improving value addition. It will generate employment in food processing, packaging, and logistics. It will boost agro-based industries and encourage local entrepreneurship. It will also improve market linkages for farmers to sell their produce at competitive prices.

Sir, through you, I would urge the hon. Union Minister of Food Processing Industries to sanction a Food Processing Cluster in Tenkasi under PMKSY ensuring financial and logistical support to develop this much-needed infrastructure. Thank you, Sir.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an important issue today.

Sacks of half-burnt currency bundles were found on the residential premises of Justice Yashwant Varma, the second senior-most judge of Delhi High Court on 14th March. Though, the matter came to the notice of the Delhi High Court Chief Justice on 15th March, it came to the public knowledge only after a week when an English daily published it. There have been curious developments since then.

The Fire Service and the Delhi Police report to the Union Home Minister. When did he come to know about it? Why did he keep silent even though the Parliament was in Session?

(1335/UB/RV)

Why did he keep silent even though Parliament was in Session? Why did the Delhi Fire Service Chief make a statement that not a penny was seized? Was it because of the judge? Was it a statement made with the knowledge and consent of the Union Minister?

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Madam, you have already made your point. Please conclude.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): In an unprecedented move, the Supreme Court uploaded the videos and pictures of the burnt currency notes on its official website. On whose instruction did the National Informatics Centre, which is managing the Supreme Court website, publish the videos and photos?

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं भी एक बहुत ही गम्भीर विषय आपके सामने ला रहा हूं। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुम्बई शहर की सीमा पर पश्चिम-उत्तर दिशा में भयंदर महानगरपालिका क्षेत्र है। उसमें काशीगांव नामक एक गांव है। उस गांव की एक जमीन मोइनुद्दीन निज़ामुद्दीन नामक एक व्यक्ति के नाम से थी। जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वह पाकिस्तान चला गया। ऐसी प्रॉपर्टी को हमारे यहां 'एनेमी प्रॉपर्टी' कहा जाता है। The enemy property is there at Mira Bhayandar. उस प्रॉपर्टी के मालिक निज़ामुद्दीन की मृत्यु हो गयी। उसके बाद उसकी पत्नी हिन्दुस्तान आई। यह सब बताकर उसने पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान का बॉण्ड, पाकिस्तान का स्टाम्प पेपर लेकर हमारे महानगरपालिका क्षेत्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर उस जमीन का मालिकाना हक़ उसके पास है, ऐसा बताया।

सर, उस पेपर पर इन्होंने उस प्रॉपर्टी को उसके नाम कर दिया और अब वह प्रॉपर्टी बेची जा रही है। बार-बार उसकी शिकायत की गयी, लेकिन उसके ऊपर वहां के कमिश्नर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय से इसके बारे में पत्र गया, फिर भी वहां के कमिश्नर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, और न ही एस.पी. कार्रवाई करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार उस प्रॉपर्टी को 'एनेमी प्रॉपर्टी' मानकर उस पर ध्यान दे और उस प्रॉपर्टी को अपने अन्तर्गत ले।

*SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR): Thank you, Chairperson Sir.

This is a momentous day. Today, on the 27th of March, Jayrambati is finally going to be connected by rail. I would like to thank the honourable Railway Minister. I would only like to mention that Jayrambati is the birthplace of Maa Sarada. Thankfully, after so many years, rail services will commence in Jayrambati. I expect the train service will connect Bishnupur and Jayrambati and it will run twice a day.

I request the Honourable Railway Minister to start train services from Bankura to Howrah via Moshagram which will run once daily. I will once again thank the Honourable Railway Minister and offer my respects to Maa Sarada.

God Bless all.

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : माननीय सभापति महोदय, मैं काफी दिनों से इसके बारे में बात करना चाहती हूं। आज मुझे मौका मिला है। यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है, यह सभी को पता है।

---

* Original in Bengali

महोदय, मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूं और मैं न सिर्फ मेवाड़ की, बल्कि पूरे देश की जनता की बात यहां रखना चाहती हूं। सपा के जो सांसद हैं, उन्होंने महाराणा सांगा के लिए बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है। महाराणा सांगा को किसी के प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो बार इब्राहिम लोदी को हराया था और एक बार उन्होंने बाबर को भी हराया था। उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते-लड़ते अपनी जान दे दी थी।

मेरा यही कहना है कि अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात न करें। जिसका भी मन आता है, कोई भी इतिहास के किसी व्यक्ति का नाम लेकर, चाहे वह मीरा मां हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हों, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब यह बात राज्य सभा में उठी थी तो सांसदों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो यह बात यहां तक नहीं पहुंचती।… (व्यवधान)

(1340/GG/GM)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है, वह सिर्फ मेवाड़ का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से वह निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोधी को दो-दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने सौ युद्ध लड़े और सौ के सौ युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कुछ लोग तुष्टीकरण के चक्कर में ऐसी बातें करते हैं। ये वही लोग हैं, जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोकने जाते हैं। महोदय, इनकी चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। … (व्यवधान)

श्री अमरा राम (सीकर) : सभापति महोदय, राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। जो 457 महाविद्यालय, जो फोर ईयर का कोर्स कराते हैं, जिसमें बीए-बीएड और बीएससी-बीएड होती है, उन 457 महाविद्यालयों को निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के तहत बदलना था और फरवरी 2025 में उनसे एप्लिकेशन भी ले ली गई और दो-दो लाख रुपये भी ले लिए गए। जबकि तीन तारीख तक उनको परमिशन एनसीईआरटी की तरफ से मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह आज तक नहीं मिली है। लाखों विद्यार्थी, जो इस कोर्स में जाना चाहते हैं, राजस्थान में और विशेष तौर से मेरे लोक सभा क्षेत्र में इन 457 में से 200 महाविद्यालय वहां हैं, वहां के विद्यार्थियों के लिए, वहां के स्ट्रक्चर के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत इसको किया जाए। … (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : शुक्रिया सर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते। सर, सरकार से मेरी यह गुज़ारिश है, हमारी सरकार दावा करती है कि जम्मू-कश्मीर में हमने पिछले पांच सालों में

काफी डेवलपमेंट की हैं। आपने आंध्र प्रदेश और बिहार में पैकेज दिया। लेकिन पैकेज की ज़रूरत जम्मू-कश्मीर को है। वहां तीस सालों से मिलिटेंसी की वजह से तबाही है, जहां सब कुछ लुट चुका है। उसके बदले में जब आप इस साल का एलोकेशन देखेंगे, आपने पिछले साल के एलोकेशन से एक हज़ार करोड़ रुपये से कम एलोकेट किया है, ज्यादा नहीं दिया है। हमारे सीएम साहब शायद कहने से थोड़ा शर्माते हैं। उन्हें क्या इश्यूज़ हैं, वह हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गुज़ारिश है कि जम्मू-कश्मीर को अपना पूरा शेयर दिया जाए। अक्सर इस हाउस में कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। यह डबल इंजन क्या होता है? If we are all under oath, फिर सारे लोग बराबर हैं, सारे स्टेट्स बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। आप क्यों किसी एक स्टेट को पैकेज देंगे और दूसरे को नहीं देंगे? मेरी यह गुज़ारिश है कि जम्मू-कश्मीर मिलिटेंसी अफेक्टिड स्टेट है, जम्मू-कश्मीर को ले कर आपके दावे पूरी तरह से गलत हैं, वहां पर आप एक स्पेशल पैकेज दीजिए। यह हमारी गुज़ारिश है।

(1345/SRG/MY)

SHRI PUTTA MAHESH KUMAR (ELURU): Sir, in our constituency, we are having a Kolleru Lake, where almost three lakh people around the Kolleru lake live for a long time. Kolleru Lake has been a bird sanctuary where birds come from different countries and live there. Today, because of the Supreme Court, they are defending the borders of the Kolleru Lake where there is a lot of farmers' individual land, which is almost 14 acres plus seven acres, almost 22,000 acres. This land has been taken over which is in this Kolleru Lake. We have requested the Supreme Court to see that the individual farmers' land should not be included in the Kolleru region, but it has not been paid attention to.

Sir, our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu and Shri Pawan Kalyan Garu also have taken up this initiative to solve the issue of Kolleru lake, which is pending for the last 20 years now where four lakh people are suffering. Till today, they do not know whether they will be living there or they will be moved from there.

I requested the Environment, Forest and Climate Change Minister to look into this issue. I met him twice to solve this issue. I again request the Environment, Forest and Climate Change Minister to solve this issue.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं पहाड़ी क्षेत्र, देव भूमि हिमाचल प्रदेश के रेलवे का विषय उठाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद पूरे देश भर में रेलवे का बजट लगभग दस गुना बढ़ा है। इसका लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश को भी मिला है। भानुपाली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन आज तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन राज्य की सरकार अपनी हिस्सेदारी नहीं दे रही है। इससे दिक्कत हो रही है।

दूसरा, नांगल-ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना तक मोदी जी की सरकार ने बना दी, लेकिन पंजाब की सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं कर रही है, इसके कारण यह रेल लाइन आगे नहीं बन पा रही है। महोदय, हमारी जो ट्रेन चलती हैं, माननीय मोदी जी ने चौथी वंदे भारत ट्रेन पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को दी है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हिमाचल एक्सप्रेस, ऊना एक्सप्रेस और हरिद्वार की ट्रेन में कुछ दिक्कतें हैं। इन ट्रेनों की साफ-सफाई बिलकुल भी नहीं है। इन ट्रेनों में बहुत पुराने डिब्बे लगे हुए हैं। फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी के डिब्बे की हालत बहुत ही खराब है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन ट्रेनों के डिब्बे को और बेहतर किया जाए, साफ-सफाई और अच्छी की जाए, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, हम जानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन देश के अनेक गांवों में पढ़ने के लिए संसाधन नहीं हैं। कई छात्र आर्थिक तंगी और उचित अध्ययन के वातावरण के अभाव में अपनी पूरी क्षमता से नहीं पढ़ पाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए किताबें और रीडिंग स्पेस की कमी के कारण उनको काफी दिक्कतें होती हैं। इससे उनका बहुत ही नुकसान होता है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर गांव में रीडिंग रूम और लाइब्रेरी स्थापित की जाए। वहां अध्ययन का वातावरण ऐसा बनाया जाए कि स्कूली बच्चों के साथ-साथ यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में उनको सुविधा मिल जाए।

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि लोक महत्व के मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भीलवाड़ा को नई दिल्ली वाया जयपुर से जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। वर्तमान में भीलवाड़ा से दिल्ली तक केवल एक ट्रेन चेतक एक्सप्रेस है। इसके कारण इस रूट पर भारी दबाव रहता है। वर्तमान में नई दिल्ली से अजमेर शताब्दी ट्रेन संख्या 12015/12016 चलती है, जो नई दिल्ली से अजमेर और अजमेर से दिल्ली आती है। मेवाड़ क्षेत्र के वासियों की मांग है कि इस ट्रेन के समय में थोड़ा परिवर्तन करके भीलवाड़ा तक बढ़ाया जाए।

महोदय, इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20979 वंदे भारत उदयपुर से जयपुर तक संचालित होती है। इस ट्रेन को उदयपुर से प्रात: जल्दी प्रारंभ करके दिल्ली तक बढ़ाया जाए।

(1350/CP/RCP)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सर, संविधान खतरे में है। आर्टिकल 14, 15 और 49, मैं आर्टिकल 49 के बारे में आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 49ए कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, उसका रख-रखाव, उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। इस देश में दो ऐसे एक्ट बने, वर्ष 1991 में प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं को कहता है कि आप अपने आपको कंट्रोल कर लीजिए और वर्ष 1995 में एक ऐसा एक्ट उसी सरकार ने बनाया, जिसमें कहा कि वक्फ बाई यूजर, जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे, वह सम्पत्ति उसकी है। इसके आधार पर एएसआई की जितनी सम्पत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मदरसे हैं, जो संसाधन हैं, उन सभी पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनकी दुकान हो गई। यह जो मेंटेलिटी है, आर्टिकल 49 का जो यह उल्लंघन है, यह वर्ष 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया। आप उसको सम्पत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे

रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं।... (व्यवधान) आप उसको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आप अपना पॉइंट रखिए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 49 और आर्टिकल 14, 15 को लागू करिए और मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है, उसको समानता के अधिकार में बदलिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

*SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Hon'ble Chairman, thank you. Sir, Maharashtra's farmers have landed in trouble. PWD Minister has resigned and Agriculture Minister is facing different allegations. Our farmers are in distress. Sir, sugarcane is not getting remunerative price. Recovery rates are fixed but the tonnage should be fixed by the respective sugar mills and must be paid at least within 15 days.

Milk rates should also be hiked. Cow milk must get Rs. 40-45 per litre. MSP should also be fixed. Around 12% GST is being charged on agriculture equipments, fertilizers, seeds etc. but, it must be cancelled immediately.

PM Kisan Yojana assistance should also be increased. Farmers and youth must get loan without considering CIBIL score. Grape growers in Solapur must get more grant and irrigation subsidy should also be credited at earliest. Thank you.

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : सर, धन्यवाद। मेरा विषय अगर दो मिनट से ज्यादा होगा, तो please do not interrupt.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Take one minute, please.

SHRIMATI HEMA MALINI (MATHURA): Thank you so much, hon. Chairperson for this opportunity to speak about something that is affecting our film industry, which I proudly belong to, in a dangerously negative way.

I refer here to the Al and deepfake technology that has swept the world. While the pros of this technology are many, the consequences target, among others, celebrities belonging to the film industry. These celebrities have worked very hard for decades to make a name, gain fame and popularity.

Many of us have become victims of this ruthless misuse, which creates multiple fake videos tarnishing the image of the persons concerned. These go viral and cause tremendous impact on the victims' mental health. This cannot be taken lightly. Another misuse of social media by callous, brutal people has surfaced with

* Original in Marathi

wicked comments on the personal lives of celebrities, often twisting facts to suit their new narratives.

(1355/NK/PS)

*DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Hon'ble Chairperson, I would like to draw the kind attention of the government through you towards the challenges that are being faced in the implementation of Fourth Phase of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in my Davanagere district.

Sir, under the Phases 1,2,3 and 4 of the PMGSY very good progress has been made and nearly 788.45 km rural roads were constructed.

So it has contributed a lot for the better connectivity, social progress and economic growth.

However, Sir, from December 2024, the guidelines were issued for the phase 4 of PMGSY. According to the new norms, Only the villages with no connectivity and also has population of 500 and more as per the 2011 census would be selected to build new road under the PMGSY.

So, I would like to know whether any provision is made for construction of alternative roads to the villages which already having the road connectivity.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को सदन और सरकार के संज्ञान में लाने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है। आज किसान को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। मुजफ्फ़रनगर में फर्जी खाद, फर्जी बीज और फर्जी पेस्टिसाइड बनाकर पूरे देश में सप्लाई की जा रही है। यही नहीं 27 रुपये क्विंटल की राख 1500 रुपये क्विंटल बेची जा रही है। उसको पोटाश बनाकर बेचा जा रहा है, उसको इफको, कृभको, आईपीएल सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं भी इसे खरीदकर बेच रही है। जिप्सम जो एक रुपये किलो है, उसको डाई बनाकर बेचा जा रहा है, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, इन लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ रही है लेकिन किसान बर्बाद हो रहा है। सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वे बाजार को लूटवा रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वे मिल पर धरना देकर बैठें।

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Hon. Chairperson, Sir, through you, I wish to draw the attention of this House to an urgent matter concerning the pending Central share contribution of Rs. 96.49 crore for the Maharashtra State Co-operative Tribal Development Corporation Limited for the financial year 2018-19.

The Maharashtra State Co-operative Tribal Development Corporation plays a vital role in uplifting and empowering tribal communities through various financial assistance and development programmes. However, the lack of timely disbursement

* Original in Kannada

of the Central share, which constitutes 49 per cent of the total authorized capital of Rs. 200 crore, has severely hampered its ability to implement key welfare initiatives effectively.

I urge the hon. Minister and the authorities concerned to take immediate action for the release of the pending funds at the earliest. Timely disbursement is crucial for ensuring seamless execution of various tribal welfare programmes.

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, बिहार में उर्दू भाषा की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहां बड़ी संख्या में उर्दू बोलने और पढ़ने वाले लोग हैं। इसके बावजूद दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया और महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में अभी तक उर्दू विभाग की स्थापना नहीं की गई है। यह आवश्यक है कि इन दोनों केन्दीय विश्वविद्यालयों में उर्दू विभाग की स्थापना की जाए ताकि उर्दू भाषा और साहित्य में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को उचित अवसर मिल सके। इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए, जिससे इन विद्यालयों में उर्दू शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

अत: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया और महत्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में जल्द से जल्द उर्दू विभाग की स्थापना की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

I stand before you today to address a pressing issue that has been causing an immense inconvenience and is danger to the public.

The National Highway-69, especially stretches from Banavara to Huliyar in Arsikere Taluk, which falls under my constituency, has to be fully completed.

Even though the project was initially started in 2018, the closure of the project was supposed to happen by 2020. But the work remains unfinished till date.

(1400/SJN/SMN)

There are four critical reaches under my Constituency the where work is still pending. They are Shaanegere, Ganjigere, Kallusadharahalli and Kanakatte.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Sir, I will conclude with last one line.

These delays have led to repeated accidents on the stretch putting lives at risk daily. Vehicles cannot pass smoothly and ambulances carrying patients are facing tremendous difficulties and, further endangering lives.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, gold is one of the most preferred asset classes for Indians and many Indians take loans against gold. But a recent directive from the RBI has made this process difficult. When people take loans against gold from banks, all they had to do was only to pay the interest regularly and

renew the loan. But, now, what the RBI has said is in order to renew the loan, for one day, you must redeem the entire gold by paying the principal and then come back the next day, pledge the gold and again renew the loan. The whole purpose is defeated because the people have to go to the private financiers for that one day to get the loan closed and then to renew it.

So, I would urge the Finance Ministry and the RBI to withdraw this directive and allow people to renew their loans as they are paying their interest on time.

1401 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के झबरकिया गांव का निवासी राजकुमार जाट, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। गुजरात राज्य के राजकोट में गोंडल विधान सभा क्षेत्र में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे देश के जाट समाज में भारी रोष है। इस मामले में गुजरात पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। हमने गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराया है।

राजकुमार जाट हत्याकांड की वजह से जाट समाज में भारी रोष है, मेरी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। वहां के पूर्व विधायक ... (*Expunged as ordered by the Chair*) और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। केन्द्र सरकार एक अच्छा मैसेज दे और इसकी घटना की सीबीआई जांच कराई जाए।

1402 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोज़पुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले छोटे किसानों की समस्याओं को उठाने का मौका दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कंटीले तार के पार जिनकी जमीनें हैं, वे छोटे किसान हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब बाढ़ आती है, तो उनकी जमीनें खुर्द-बुर्द हो जाती हैं। दूसरा, पाकिस्तान की ओर से जंगलों से जो आवारा पशु आते हैं, वे उनकी पूरी फसलों को तबाह कर देते हैं।

इससे पहले केन्द्र सरकार की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था। पिछले तीन सालों से वह मुआवजा बंद पड़ा है, उसको नहीं दिया जा रहा है। 10,000 रुपये से किसानों का कुछ भला नहीं होगा। मेरी सरकार से मांग है कि वह किसानों को कम से कम प्रति वर्ष 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे, ताकि उन किसानों की जिंदगी अच्छी तरह से बसर हो सके। सरकार से मेरी यही मांग है। तीन साल के बकाया पैसे नहीं दिए हैं, 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वे पैसे उन किसानों को दिए जाएं।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shrimati Mahima Kumari Mewar	Dr. Manna Lal Rawat Shri Rao Rajendra Singh
Shri Balwant Baswant Wankhade	Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Rajabhau Parag Prakash Waje

	Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Shri Bajrang Manohar Sonwane Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar
Shri Rajabhau Parag Prakash Waje	Shri Nilesh Dnyandev Lanke Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare Shri Bajrang Manohar Sonwane
Dr. Shivaji Bandappa Kalge	Dr. Prashant Yadaorao Padole Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar
Shri Rajmohan Unnithan	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Adv. Chandra Shekhar	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Karti P. Chidambaram	Dr. Prashant Yadaorao Padole
Shri Kalyan Banerjee	Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar
Shri Manish Tewari	Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar
Sushri Praniti Sushilkumar Shinde	Shri Shrirang Appa Chandu Barne Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	Shri Arun Nehru Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian
Shri Murasoli S.	Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian Shri Arun Nehru Shri Tamilselvan Thanga
Shri Parshottambhai Rupala	Shri Shrirang Appa Chandu Barne
Shri Rajesh Ranjan	Shri Shrirang Appa Chandu Barne
Shri Sandipanrao Asaram Bhumare	Shri Shrirang Appa Chandu Barne
Shri Chandra Prakash Joshi	Shri Shrirang Appa Chandu Barne Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar
Dr. Nishikant Dubey	Shri Shrirang Appa Chandu Barne